

LOK SABHA

POSITION NO.

UNSTARRED QUESTION

ORAL

QUESTION ADMITTED FOR

ANSWER

WRITTEN

FOR

10 FEB 2020

20

Payment by RuPay Cards

1161. SHRI KANUMURU RAGHU RAMA
KRISHANA RAJU:

Will the Minister of FINANCE

वित्त मंत्री

be pleased to state:

(a) whether the Government is aware that RuPay debit cards being issued by the banks are not working for payment in Bharatkosh;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) whether any corrective action has been taken in this regard and if so, the details thereof?

CGA

SRB
2/2

AMCGA (HRAD)



**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
O/o CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS**

**LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 1161
TO BE ANSWERED ON Monday, The 10th February, 2020
Magha 21, 1941(Saka)**

“Payment by RuPay Cards”

1161. Shri KANUMURU RAGHU RAMA KRISHANA RAJU

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Government is aware that RuPay debit cards being issued by the banks are not working for payment in Bharatkosh;**
- (b) if so, the details thereof and reasons therefor; and**
- (c) whether any corrective action has been taken in this regard and if so, the details thereof?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE (Finance & Corporate Affairs)
(Shri ANURAG SINGH THAKUR)**

(a)

RuPay debit Card having been enabled on Bharatkosh, no stakeholder has reported the non working of RuPay debit cards for payments in Bharatkosh.

(b) & (c)

Not applicable in view of reply to (a) above.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1161

उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020

21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है।

रुपे कार्डों द्वारा भुगतान

1161. श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे रुपये डेबिट कार्ड भारत कोष में भुगतान के लिए काम नहीं कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्यमंत्री (वित्त और कारपोरेट कार्य)

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क)

रुपे डेबिट कार्ड भारतकोष पर कार्य करने के लिए सक्षम हैं, किसी भी हितधारक ने रुपये डेबिट कार्डों के भारतकोष में भुगतान के लिए काम न किए जाने की सूचना नहीं दी है।

(ख) एवं (ग)

उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

LOK SABHA

POSITION NO.

UNSTARRED QUESTION

ORAL

QUESTION ADMITTED FOR

ANSWER

WRITTEN

FOR

10 FEB 2020.....20

Public Financial Management System

1276. SHRI VISHNU DAYAL RAM:

Will the Minister of FINANCE

वित्त मंत्री

be pleased to state:

(a) the objectives of the Public Financial Management System;

(b) the details of functionalities that have been and are proposed to be built into it and its various functions; and

(c) the details of other expenditure reforms that have been implemented by the Government?

4/2

CGA

Sd/-
5/2

Asst. CGA (HR&O)



**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
O/o CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS**

**LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 1276
TO BE ANSWERED ON Monday, The 10th February, 2020
Magha 21, 1941(Saka)**

“Public Financial Management System”

1276. Shri VISHNU DAYAL RAM

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) the objectives of the Public Financial Management System;**
- (b) the details of functionalities that have been and are proposed to be built into it and its various functions; and**
- (c) the details of other expenditure reforms that have been implemented by the Government?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE(Finance & Corporate Affairs)
(Shri ANURAG SINGH THAKUR)**

- (a) The objective of Public Financial Management System (PFMS) is to facilitate sound public finance management for Government of India by establishing an efficient fund flow system as well as a receipt and payment cum accounting system. PFMS provides various stakeholders with reliable and meaningful management information and an effective decision support system**
- (b) Reply given in Annexure-I**
- (c) Reply given in Annexure-II**

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1276

उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020

21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है।

‘सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली’

1276. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इसमें शामिल की गई और प्रस्तावित कार्यक्षमताओं तथा इसके विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए अन्य व्यय सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्यमंत्री (वित्त और कारपोरेट कार्य)

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ एक प्राप्ति एवं भुगतान सह लेखांकन प्रणाली की स्थापना करके भारत सरकार के लिए सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करना है। पीएफएमएस विश्वसनीय तथा सार्थक प्रबंधन सूचना से युक्त विभिन्न हितधारक तथा एक कारगर निर्णय सहायता प्रणाली मुहैया कराता है।

(ख)

इसका उत्तर अनुबंध - I में दिया गया है।

(ग)

इसका उत्तर अनुबंध - II में दिया गया है।

For Lok Sabha Unstarred Question No. 1276

(b) Functionalities

Modules developed /under development by Public Financial Management System (PFMS) for stakeholders as per the mandate above include:

I. Fund Flow Monitoring

- (a) Agency Registration Module**
- (b) Expenditure, Advance and Transfer (EAT) module**
- (c) Accounting Module for registered agencies**
- (d) Treasury Interface Module**
- (e) Public Financial Management System – Panchayati Raj Institutions (PFMS-PRI) Fund Flow Interface**
- (f) Mechanism for State Scheme for fund tracking**
- (g) Monitoring of Externally Aided Projects (EAP)**

II. Direct Benefit Transfer Modules

- (a) Pay & Accounts Office(PAO) to Beneficiaries**
- (b) Agency to Beneficiaries**
- (c) State Treasuries to Beneficiaries**

III. Interfaces for Banking

- (a) Core Banking Solution(CBS)**
- (b) India Post**
- (c) Reserve Bank of India (RBI)**
- (d) Regional Rural Banks (RRBs)**
- (e) Cooperative Banks.**

IV. Pay & Accounts Office (PAO) module of PFMS covers payment and accounting of all Pay and Accounts Offices bills

V. Employees Information System (EIS) Module has been developed and made operational for processing of salary bills of all Drawing and Disbursing Officers(DDOs)

VI. Cheque Drawing and Disbursing Officers (CDDO) Module covers payment and accounting functions of CDDO bills.

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1276 के लिए

(ख) कार्यकलाप

उपर्युक्त अधिदेश के अनुसार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा हितधारकों के लिए विकसित किए गए/विकसित किए जा रहे मॉड्यूलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. निधि प्रवाह निगरानी

- (क) एजेंसी पंजीकरण मॉड्यूल
- (ख) व्यय, अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल
- (ग) पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेखांकन मॉड्यूल
- (घ) कोषागार इंटरफेस मॉड्यूल
- (ङ) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली - पंचायती राज संस्थाएं (पीएफएमएस-पीआरआई) निधि प्रवाह इंटरफेस
- (च) राज्य स्कीम के लिए फंड ट्रेकिंग हेतु तंत्र
- (छ) बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं की निगरानी (ईएपी)

II. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉड्यूल

- (क) वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) से लाभार्थियों तक
- (ख) एजेंसी से लाभार्थियों तक
- (ग) राज्य कोषागार से लाभार्थियों तक

III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस

- (क) कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)
- (ख) भारतीय डाक
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
- (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- (ङ) सहकारी बैंक

IV. पीएफएमएस के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) मॉड्यूल में सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों के बिलों का भुगतान और लेखांकन शामिल है।

V. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के वेतन बिलों की प्रोसेसिंग के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे चालू किया गया है।

- VII. Non-Tax Receipt Portal (NTRP) as one-stop window to citizens/corporates/institutions/other users for making online deposits of Non-Tax receipts (NTR) which are payable to the Government of India (GOI)**
- VIII. Complete online processing of pension disbursement through integration of Bhavishya (Department of Pension) and Pension Authorisation Retrieval & Accounting System (PARAS) software of Central Pension Accounting Organization (CPAO).**
- IX. General Provident Fund (GPF) Module covers all the functionalities of GPF like GPF advance, withdrawal, final payment, interest calculation etc.**
- X. Integration of PFMS with the following standalone applications. The sanction generated through the standalone application being captured in the PAO module of PFMS**
- **Government e-Marketplace (GeM)**
 - **PRAHARI of Boarder Security Force (BSF)**
 - **SELO of Central Reserve Police Force (CRPF)**
 - **E-Wisdom of Lok Sabha**
 - **Composite Financial Accounting System (CFAS) of UT Chandigarh**
 - **Indian Customs Electronic Commerce Gateway (ICEGATE) of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC).**
 - **Department of Atomic Energy**
 - **Department of Space**

- VI. चैक आहरण एवं वितरण अधिकारी (सीडीडीओ) मॉड्यूल में सीडीडीओ बिलों का भुगतान एवं लेखा कार्य शामिल होते हैं।
- VII. कर-भिन्न प्राप्तियां (एनटीआर) जोकि भारत सराकर को देय होती हैं, को ऑनलाइन जमा कराने के लिए नागरिकों/ कार्पोरेट/संस्थाओं/ अन्य प्रयोक्ताओं के लिए एकल-समाधान खिडकी के रूप में कर-भिन्न प्राप्त पोर्टल (एनटीआरपी) बनाया गया है।
- VIII. भविष्य (पेंशन विभाग) तथा केंद्रीय पेंशन लेखा संगठन (सीपीएओ) के पेंशन प्राधिकार रिट्रीवल एवं लेखांकन प्रणाली (पीएआरएएस) के एकीकरण के जरिए पेंशन वितरण की संपूर्ण ऑनलाइन प्रोसेसिंग किया जाना।
- IX. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) मॉड्यूल में जीपीएफ के सभी कार्यकलाप जैसे जीपीएफ अग्रिम, आहरण, अंतिम भुगतान, ब्याज आकलन आदि शामिल होता है।
- X. पीएफएमएस का निम्नलिखित स्टैंडअलोन एप्लीकेशनों के साथ एकीकरण। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के जरिए जनरेट की गई मंजूरी को पीएफएमएस के पीएओ मॉड्यूल में लिया जा रहा है।
- गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (जीईएम)
 - सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का प्रहरी
 - केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ) का सेलो
 - लोकसभा का ई-विसडम
 - संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की संयुक्त वित्तीय लेखा प्रणाली (पीएफएएस)
 - केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रानिक कॉमर्स गेटवे (आईसीईजीएटीई)।
 - परमाणु ऊर्जा विभाग
 - अंतरिक्ष विभाग

(c) Other Expenditure Reforms

- i. Majority of schemes/components being implemented across Ministries/Departments such as PAHAL, MGNREGS, PMAY (Gramin), Pensions and Scholarships, which involves cash transfer as well as in kind transfers such as food grains and Mid-Day Meals to school children, have been linked to Direct Benefit Transfer (DBT). Implementation of Aadhaar based DBT has resulted in significant savings due to removal of duplicate/fake beneficiaries.**

- ii. Government-e-Marketplace (GeM) portal has been launched by Department of Commerce (DGS&D) on 9th August, 2016 which is a complete end-to-end procurement solution for common use goods & services for Government buyers. More than 31000 products and 1215 service providers have been made available for purchase/hire by the Government users.**

- iii. Revised General Financial Rules (GFRs) 2017 has been released on 7th March, 2017 with updated limits and provision.**

(ग) अन्य व्यय सुधार

- i. मंत्रालयो/विभागों में कार्यान्वित की जा रही अधिकांश स्कीमों/संघटकों जैसे कि पहल, एमजीएनआरईजीएस, पीएमएवाई (ग्रामीण), पेंशन और छात्रवृत्तियां, जिनमें नकदी अंतरण के साथ-साथ वस्तु अंतरण जैसे कि विद्यालयी छात्रों के लिए अनाज और मध्याह्न भोजन, को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के साथ जोड़ा गया है। आधार आधारित डीबीटी के परिणामस्वरूप दोहरीकरण/जाली लाभार्थियों के समाप्त होने से अत्यधिक बचतें हुई हैं।
- ii. वाणिज्य विभाग (डीजीएसएंडडी) द्वारा 09 अगस्त, 2016 को गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस पोर्टल आरंभ किया गया है जो सरकारी क्रेताओं के लिए सामान्य प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं की सीधी (एंड टू एंड) अधिप्राप्ति का संपूर्ण समाधान है। सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा खरीदारी/भाड़े के लिए 31000 उत्पाद तथा 1215 सेवा प्रदाता से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं।
- iii. 07 मार्च, 2017 को नवीनतम सीमाओं तथा प्रावधान से युक्त संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 जारी की गई है।

RAJYA SABHA

POSITION NO.

UNSTARRED QUESTION

ORAL

QUESTION ADMITTED FOR

ANSWER

WRITTEN

FOR

11 FEB 2020 20

Non-working of RuPay debit cards

1022. SHRI T. G. VENKATESH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that

RuPay debit cards being issued by the banks are not working for payment in BharatKoshi;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) whether any corrective actions have been taken in this regard, if so, the details thereof?

2/12

CGA - En tour

Adm. C/A (SG) may kindly see please

8
07/02/2020

Adm. (GA/CDN)

Sd/-
Sr PS to C/A
07/02/2020

20
07/2/2020

In C/A (CDN).



1296/98 (GA/SG)
07/02/2020 7/2

AEGA(CDN)
GAO(CDN)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
O/o CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS**

**RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION No. 1022
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, The 11TH February, 2020
Magha 22, 1941(Saka)**

“Non Working of RuPay debit cards”

1022. Shri T.G.VENKATESH

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether Government is aware that RuPay debit cards being issued by the banks are not working for payment in Bharatkosh;**
- (b) if so, the details thereof and reasons therefor; and**
- (c) whether any corrective actions have been taken in this regard, if so, the details thereof?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE (Finance & Corporate Affairs)
(Shri ANURAG SINGH THAKUR)**

(a)

RuPay debit Card having been enabled on Bharatkosh, no stakeholder has reported the non working of RuPay debit cards for payments in Bharatkosh.

(b) & (c)

Not applicable in view of reply to (a) above.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1022

उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2020

22 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है।

‘रुपे’ डेबिट कार्ड का काम न करना

1022. श्री टी.जी. वेंकटेश

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे ‘रुपे’ डेबिट कार्ड ‘भारतकोष’ में भुगतान के लिए काम नहीं कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्यमंत्री (वित्त और कारपोरेट कार्य)
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क)

रुपे डेबिट कार्ड भारतकोष पर कार्य करने के लिए सक्षम है, किसी भी हितधारक ने रुपे डेबिट कार्डों के भारतकोष में भुगतान के लिए काम न किए जाने की सूचना नहीं दी है।

(ख) एवं (ग)

उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता ।

.....

RAJYA SABHA

POSITION NO.

UNSTARRED QUESTION

ORAL

QUESTION ADMITTED FOR

ANSWER

WRITTEN

FOR

23 MAR 2021.....20

Issues related to CGA and DBT

3104 Prof. Manoj Kumar Jha:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

- whether the Controller General of Accounts (CGA) maintains all the details of direct benefit transfer, if so, the details of reports maintained;
- the list of all types of reports being stored by Government on direct benefit transfer; and
- the scheme-wise errors in amounts and numbers reported during direct benefit transfer to beneficiaries during financial year 2020-2021?

CGA

17/3/21

Dy. No. RS. 1654725 / PARLITY

17/3/2021

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
O/o CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS**

**RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION No. 3104
TO BE ANSWERED ON Tuesday, The 23rd March, 2021
2 Chaitra, 1943 (Saka)**

“Issues related to CGA and DBT”

3104. Prof. MANOJ KUMAR JHA;

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- a) whether the Controller General of Accounts (CGA) maintains all the details of direct benefit transfer, if so, the details of reports maintained;**
- b) the list of all types of reports being stored by Government on direct benefit transfer; and**
- c) the scheme-wise errors in amounts and numbers reported during direct benefit transfer to beneficiaries during financial year 2020-2021?**

**ANSWER
MINISTER OF STATE (FINANCE)
(SHRI ANURAG SINGH THAKUR)**

(a) & (b)

NO.

However, the following Direct Benefit Transfer (DBT) Reports are available on Public Financial Management System (PFMS) of Controller General of Accounts for the Direct Benefit Transfer (DBT) payments processed through Public Financial Management System (PFMS) :-

- (i) ‘DBT-01’(Beneficiary Registration Status)**
- (ii) ‘DBT-04’ (District-wise DBT Transaction Summary)**
- (iii) ‘DBT-05’ (Scheme Wise DBT Transaction Summary)**
- (iv) ‘DBT-07’ (State Wise DBT Transaction Summary)**
- (v) ‘DBT-09’ (Scheme Wise Performance Report for DBT Transaction)**
- (vi) ‘DBT-16’ (PAO-DBT Payment Status)**

(c)

No such data available on PFMS.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3104
उत्तर मंगलवार, 23 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

2 चैत्र, 1943 (शक)

“महालेखा नियंत्रक और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित मुद्दे”

3104. प्रो. मनोज कुमार झा;

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क) क्या महालेखा नियंत्रक (सीजीए) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के सभी ब्यौरे का हिसाब रखता है यदि हाँ, तो ऐसी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;
- ख) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर संग्रहित की जा रही सभी प्रकार की रिपोर्ट की सूची क्या है; और
- ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभार्थियों को किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दौरान राशि और संख्याओं में योजना-वार कितनी त्रुटियां दर्ज की गई हैं?

उत्तर
राज्य मंत्री (वित्त)
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख)

जी, नहीं।

तथापि, महालेखा नियंत्रक की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के जरिए किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतानों के लिए निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रिपोर्टें उपलब्ध हैं:-

- (i) 'डीबीटी-01' (लाभार्थी पंजीकरण स्थिति)
- (ii) 'डीबीटी-04' (राज्य-वार डीबीटी लेनदेन सारांश)
- (iii) 'डीबीटी-05' (स्कीम-वार डीबीटी लेनदेन सारांश)
- (iv) 'डीबीटी-07' (राज्य-वार डीबीटी लेनदेन सारांश)
- (v) 'डीबीटी-09' (डीबीटी लेनदेन के लिए स्कीम-वार कार्य निष्पादन रिपोर्ट)
- (vi) 'डीबीटी-16' (पीएओ-डीबीटी भुगतान स्थिति)

(ग)

पीएफएमएस पर ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION

POSITION NO.

ORAL

QUESTION ADMITTED FOR

ANSWER

WRITTEN

FOR

3 APR 2018

..... 20

Rolling out of PFMS

4077. SHRI N. GOKULA-KRISHNAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has launched initiatives for PF account holders;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the Public Financial Management System (PFMS) has become a game changer in Government

business and all the modules would be rolled out by December, 2018; and

(d) if so, the details thereof? ✓

C C A

27/3

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
O/o CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS**

**RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION No. 4077
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, The 3rd April, 2018
Chaitra 13, 1940(Saka)**

“Rolling out of PFMS”

4077. Shri N. GOKULAKRISHNAN

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government has launched initiatives for PF account holders;**
- (b) if so, the details thereof;**
- (c) whether it is also a fact that the Public Finance Management System (PFMS) has become a game changer in Government busines and all the modules would be rolled out by December, 2018; and**
- (d) if so, the details thereof?**

**ANSWER
MINISTER OF STATE(FINANCE)
(SHRI P. RADHAKRISHNAN)**

(a) & (b)

Yes, Sir.

The Office of Controller General of Accounts has launched the online centralized GPF module developed on the existing PFMS platform. This module help the Government employees for mapping of their multiple GPF Accounts with the unique employee ID generated in Employees Information System. Employees are also able to view their GPF accumulations and apply online for advance/withdrawals. It also enables efficient processing of transfer in and transfer out of GPF balances electronically.

(c) & (d)

The various modules under PFMS at present are:-

- i) Central Sector/Centrally Sponsored Schemes and DBT**
- ii) Payment and Accounting module of PFMS**

As per approval the PFMS scheme has been extended till March, 2020.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4077

उत्तर मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/चैत्र 13,1940 (शक) को दिया जाना है

“पीएफएमएस का बहिर्वर्तन”

4077. श्री एन. गोकुलकृष्णन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य निधि खाताधारकों के लिए कोई पहल की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) सरकारी कारबार में निर्णायक सिद्ध हुआ है और दिसंबर, 2018 तक सभी माइयूल्स का बहिर्वर्तन (रॉल आउट) कर दिया जाएगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री (वित्त)
(श्री पी.राधाकृष्णन)

(क) और (ख)

जी, हाँ।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने ऑनलाइन केन्द्रीकृत जीपीएफ माँड्यूल आरंभ किया है जिसे मौजूदा पीएफएमएस प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है। यह माँड्यूल सरकारी कर्मचारियों की कर्मचारी सूचना प्रणाली में सृजित विशिष्ट कर्मचारी आईडी के जरिए उनके विविध जीपीएफ खातों को तैयार करने में मदद करता है। इससे कर्मचारी जीपीएफ में अपनी संचित धनराशि को देख सकते हैं और अग्रिम/ आहरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे जीपीएफ बकाया राशियों के अंतरण की कार्रवाई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुशलतापूर्वक की जा सकती है।

(ग) और (घ)

इस समय पीएफएमएस के अंतर्गत विभिन्न माँड्यूल निम्नलिखित हैं :-

- (i) केन्द्रीय क्षेत्र/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा डीबीटी
(ii) पीएफएमएस का भुगतान तथा लेखा माँड्यूल

अनुमोदन के अनुसार पीएफएमएस योजना को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।
